घोषित की थी जिसके अधीन उन गरीब विधवाओं से आवेदन पत्र मांगे गये थे जो डी०डी०ए० की 1985 की स्लम स्कीम के अन्तर्गत पंजीकृत थीं, यदि हां, तो कितनी विधवाओं ने उक्त स्कीम के अधीन आवेदन किया था ;

(ख) इस स्कीम के अधीन अब तक कितने ड्रॉ निकाले गये हैं और कितनी विधवाओं को मकान दिये गये हैं ; और

(ग) इस स्कीम के अधीन मकानों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह निर्माण कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विवरणपत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) वर्ष 1987 को बेघरों के लिये घर अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था । इस वर्ष दिल्ली में बेघरों के लिये घर का एक राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना का अभियान छेड़ा गया था । इस परियोजना के अन्तर्गत "मलिन बस्ती निवासी तथा अन्य के लिये रिहायशी फ्लैट पंजीकरण योजना–1985" के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम विंग) के पास पंजीकृत विधवाओं से प्रदर्शन परियोजना के सदस्य के रूप में अपना पंजीयन कराने के लिए विकल्प मांगा गया था और इसके अनुसरण में 625 विधवाओं ने पंजीयन के लिए आवेदन किए थे । विधवाओं के लिए 1987 में (i) स्वयं सिद्ध सहकारी सामूहिक आवास समिति तथा (ii) स्वयं सेवा सहकारी सामूहिक आवास समिति नामक दो सामूहिक आवास समितियां गठित की गई थीं जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 262 और 339 थी ।

(ख) और (ग) स्वयं सिद्ध समिति ने 262 फ्लैट की परियोजना को पूरा कर लिया है और 26–12–1990 को पहले लॉट का एक ड्रॉ निकाला है । सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् शेष सदस्यों के मामले में आवश्यक मंजूरी कर देने के तुरन्त बाद समिति द्वारा दूसरा ड्रा निकाला जायेगा ।

स्वयं सेवा सहकारी समिति की परियोजना का काम प्रगति पर बताया गया है । इस परियोजना के निर्माण में हुए विलम्ब के कारण, निधियों की कमी और पट्टा विलेख को अन्तिम रूप देने में हो रही देरी बताये गये हैं । उम्मीद की जाती है कि पट्टा विलेख शीघ्र ही निष्पादित कर लिया जायेगा । तत्पश्चात् समिति हुडको से वित्तीय सहायता के लिये पात्र हो जायेगी ।

Control of floods in Maharashtra

*163. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government has submitted any proposal to the Central Government for control of floods in the State:

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken so far in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

देश की विभिन्न नदियों का परस्पर जोड़ा जाना

*167. **श्री राम जेठमलानी**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ने के लिए स्वर्गीय डा० के० एल० राव द्वारा सुझाई गयी योजनाओं को मूर्तरूप देने का विचार

रखती है ताकि सिंचित-भूमि क्षेत्र का विस्तार किया जा सके और देश को बाढ़ के कारण होने वाली अपार क्षति से बचाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो सर्वप्रथम देश की किन-किन नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

गंगा नदी के जल को कावेरी में अंतरित करने के संबंध में डा० के०एल० राव के प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की गयी और इसे वित्तीय दृष्टि से तथा तकनीकी एवं आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया । इसके लिये जल उठाने हेतु बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता है । विकल्प के रूप में सरकार ने एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है जिसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की मुख्य नदियों को तथा हिमालयीय नदियों को अलग-अलग जोड़ने की परिकल्पना की गयी है ।

वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने पहली बार, प्राय-द्वीपीय नदी विकास के बीच निम्नलिखित 17 जल अन्तरण सम्पर्कों पर अध्ययन किए हैं :—

1. महानदी—बूढ़ाबलंग
2. महानदी—गोदावरी
3. इन्द्रावती—वेनगंगा
4. वेनगंगा—कृष्णा
5. कृष्णा—पेन्नार
6. पेन्नार (गांडीकोटा)—पलार—कावेरी
7. कावेरी—वैगई
8. गोदावरी (इंचमपल्ली)—कृष्णा (नागार्जुनसागर)
9. कृष्णा (नागार्जुनसागर)—पेन्नार—सोमासिला
10. पेन्नार (सोमासिला) पलार—कावेरी कोलेरून
11. गोदावरी (इंचमपल्ली)—कृष्णा (पुलिचिन्ताला)
12. गोदावरी (पोलावरम)—कृष्णा—(विजयवाड़ा)
13. पार-तापी
14. दमनगंगा—तप्ती
15. केरल और कर्नाटक की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां (पश्चिम पूर्व संपर्क)
16. केन—बेतवा
17. पार्वती—कालीसिंध—चम्बल

अभिकरण ने निम्नलिखित 7 जल अन्तरण सम्पर्कों पर प्रारम्भिक रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली है :—

(i) महानदी—गोदावरी—(दोवालि-स्वरम)

(ii) गोदावरी (पोलावरम)—कृष्णा (विजयवाड़ा)

(iii) पार-तापी

(iv) पम्बा—अचनकोविल (केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी) को वैगई से (तमिलनाडु में पूर्व की ओर बहने वाली नदी)

(v) केन—बेतवा

(vi) गोदावरी (इंचमपल्ली)—कृष्णा (पुलिचिन्ताला)

(vii) पार्वती—कालीसिंध—चम्बल

ऐसा देखा गया है कि इनमें से, पम्बा—अचनकोविल—वगई, पार-ताप्ती और केन—बतवा के बीच जल अन्तरण सम्पर्कों

का इस समय तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाए जाने की संभावना है । पम्बा–अचनकोविल–वैगई सम्पर्क पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है ।

Shortage of foodgrains in Orissa

*169. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item under the caption "Orissa foodgrains scenario bleak" as published in the Hindustan Times dated 26th August, 1991;

(b) if so, whether Food Corporation of India is responsible for lack of coordination and mismanagement in many depots of the Corporation; and

(c) what steps Government have taken so far to ensure regular supply of rice, wheat and other cereals to the poor and tribals of Koraput, Phulbani, Mayurbhanj and Keonjar districts in Orissa where the FCI depots are reportedly found to be out of stocks of foodgrains at present?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) It has been reported by the Food Corporation of India that the lifting of rice, and wheat in the four districts of Orissa upto July, 1991 in the current financial year has been satisfactory but it did suffer somewhat during August, 1991. The Corporation has been asked to undertake inter-district movement to supplement despatches from Punjab and Haryana so that balance of allocations made for August 1991 are lifted by the State Government during the current month.

Incentives for production of wheat in Madhya Pradesh

*170. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of Madhya Pradesh grows the best quality of wheat in the country;

(b) whether it is also a fact that demand of Madhya Pradesh wheat has increased manifold throughout the country; and

(c) if so, what incentives Government propose to give to the cultivators or to the State of Madhya Pradesh for better wheat cultivation in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) and (b) Wheat varieties like C.306, Sujata, Mukta and local Malvi etc., produced in the State of Madhya Pradesh and adjoining areas of Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are in demand due to good physical appearance and cooking quality.

(c) A Centrally Sponsored Special Foodgrains Production Programme for wheat with 100 per cent assistance from Government of India is under implementation since 1988-89 in the State of Madhya Pradesh for increasing the production and productivity in 21 selected districts. The fund allocated for Madhya Pradesh for the year 1991-92 is Rs. 285 lakhs.

Theft and pilferage of Railway Materials

*171. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of thefts and pilferage of railway materials has increased considerably despite the manifold increase in the strength of Railway Protection Force;